**Dr.Vivek Mishra**
**SRAP College Bara Chakia**

# भारत में आर्थिक सुधार

## (Economic Reforms in India Since 1991)

भारत सरकार द्वारा जुलाई 1991 से अपनाई गई आर्थिक नीति नई आर्थिक नीति के नाम से जानी जाती है। स्वतंत्राता से जून 1991 तक हमारे द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतिया तीव्र आर्थिक वृद्धि के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सपफल नहीं रहीं। इसने हमें आर्थिक संकट की ओर, राजकोषीय घाटे, प्रतिकूल भुगतान संतुलन, असक्षमता और लाल फीताशाही की तरफ ढकेला। आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए और आर्थिक वृद्धि की दर को तेज करने के लिए जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति सामने आई। नई आर्थिक नीति निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है:

### सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की प्राथमिकता को कम करना (Reducing Priority Development of Public Sector)

सार्वजनिक क्षेत्र अब उच्च टेक्नोलॉजी और आधारभूत ढाचे के महत्वपूर्ण क्षेत्रा जैसे सड़कें, रेलवे, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और सीवेज सुविधाओं आदि पर ध्यान देगी। सार्वजनिक क्षेत्र को दी गई 17 उद्योगों में से 9 जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत आते हैं। ये उद्योग हैं लौह और इस्पात, विद्युत, वायु यातायात, नौका निर्माण, भारी विद्युत मशीनरी, दूर संपर्क, केबल और यंत्र–संयंत्र आदि के हैं। सरकार ने इनके अंशों को वित्तीय संस्थाओं, जनता और श्रमिकों में अंशों का कुछ भाग देने की योजना बनाई।

### विदेशी निजी निवेश के लिए खुले दरवाजे (Open Door to Foreign Private Investment)

नई आर्थिक नीति ने निजी विदेशी निवेश नीति का स्वागत किया और बाहरी निवेश पर लगे प्रतिबन्ध को हटाया। पहले विदेशी सहायता, उनकी एजेंसिया, एशियन बैंक और IMF पर प्रतिबन्ध था।

## अर्थव्यवस्था का उदारीकरण (Liberalisation of Economy)

सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और भौतिक नियंत्रण को निम्नलिखित के संदर्भ में उदार बनाया गया-

(*i*) औद्योगिक लाइसेंसिंग

(*ii*) उत्पादों की कीमत और वितरण नियंत्रण

(*iii*) आयात लाइसेंसिंग

(*iv*) विदेशी विनिमय नियंत्रण

(*v*) कंपनियों द्वारा पूजीगत व्ययों पर नियंत्रण

(*vi*) बड़े व्यापार संगठनों द्वारा निवेश पर **प्रतिबन्ध** ।

उदारीकरण नीति के पीछे मुख्य उद्देश्य कीमतों और प्रतियोगिता को अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाने देना है। सरकार ने यह महसूस किया कि ये **प्रतिबन्ध** उचित नहीं थे। ये सिर्फ भ्रष्टाचार, विलंब और अकुशलता के लिये जिम्मेदार हैं।

## अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से एकीकरण (Integration of the Economy with the World Economy)

नई आर्थिक नीति का यह मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ गहरा **सम्बन्ध** रखे। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं, टेक्नोलॉजी और अनुभव के विनिमय में आसानी हुई। अतः आयात लाइसेंसिंग पर लगे मात्रात्मक **प्रतिबन्ध** को हटाया गया। आयात चुगी की दर घटा दी गई।